



2026:AHC: 180626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1238 वर्ष 2026

निशा और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हरि ओम शरण तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बंदी (कार्पस), निशा, जिसकी आयु लगभग 24 वर्ष है, श्रीमती कसमा की पुत्री है और ऐसा अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की अवैध और गैरकानूनी निरुद्धि में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, बंदी (कार्पस) की कथित अवैध निरुद्धि के संबंध में, थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 87 और 351(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 239 वर्ष 2026 के रूप में 04.08.2026 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, पूर्वोक्त एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, न तो बंदी (कार्पस) को बरामद किया गया है और न ही उसमें नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बंदी (कार्पस) को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और इस न्यायालय से उचित अनुतोष की मांग किया है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बंदी (कार्पस) का विधिवत पता लगाया गया और उसे बरामद कर लिया गया। तत्पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 180 और 183 के अंतर्गत उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि वह प्रत्यर्थी संख्या 5, विशाल के साथ एक रोमांटिक संबंध में थी, और वह अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से उसके साथ रहने की इच्छा रखती थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि बंदी (कार्पस) को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी अवैध निरुद्धि, दबाव या प्रतिबंध के अधीन नहीं किया गया है और वह स्वेच्छा से प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ रह रही थी। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि, पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है।

मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना है और रिट याचिका के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत निर्देशों के साथ अभिलेख पर लाई गई सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों और, अधिक विशेष रूप से, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्राप्त निर्देशों से, यह स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) की जन्म तिथि 10.07.2003 दर्ज है। तदनुसार, कथित घटना की तिथि पर, बंदी (कार्पस) ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर लिया था और इसलिए, वह अपने निवास और व्यक्तिगत मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विधि में सक्षम थी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज उसके बयानों से यह भी पता चलता है कि बंदी (कार्पस) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 5, विशाल के साथ एक प्रेम संबंध में है, और वह उसके साथ रहने की इच्छा रखती है। ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है जो यह इंगित करता हो कि पूर्वोक्त बयान किसी खतरे, दबाव, अनुचित प्रभाव या किसी अन्य प्रकार की विवशता का परिणाम था। इसके विपरीत, न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री इंगित करती है कि बंदी (कार्पस) अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही है और किसी भी व्यक्ति की अवैध या गैरकानूनी अभिरक्षा में नहीं है।

निर्देशों से यह भी स्पष्ट होता है कि 24.08.2026 को बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा स्वयं बंदी (कार्पस) द्वारा व्यक्त की गई इच्छा और स्वेच्छा के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 5 के माता-पिता को सौंप दी गई थी। एक बार बंदी (कार्पस) ने, एक वयस्क और सक्षम व्यक्ति होने के नाते, उस व्यक्ति के संबंध में अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है, जिसके साथ वह रहना चाहती है, यह न्यायालय, अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, अवैध निरुद्धि या दबाव को इंगित करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, उसे उसकी व्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध किसी स्थान या किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए विवश नहीं कर सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग करने वाली याचिका में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से निरुद्धि की वैधता से संबंधित है। वर्तमान वाद में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री बंदी (कार्पस) की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी अवैध अभिरक्षा या गैरकानूनी प्रतिबंध के अस्तित्व को प्रकट नहीं करती है। बल्कि, अभिलेख यह प्रदर्शित करता है कि उसने स्वेच्छा से अपना निवास स्थान चुना है और प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त किया है।

पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदी (कार्पस) एक वयस्क है और उसने स्वेच्छा से प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त किया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए, वर्तमान याचिका में कोई गुण-दोष नहीं है और तदनुसार, इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

31 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”